



Economic Survey Brahmastra

आर्थिक समीक्षा राजस्थान 2025-26

अध्याय 5 — औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि

Chapter 5 — Industry, Mining & Economic Growth

RAS 2026 — प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा · द्विभाषी (हिन्दी + English)
संपूर्ण तथ्य · सभी डेटा टेबल · योजनाएँ · अभ्यास प्रश्न

यह सामग्री राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 पर आधारित है तथा RajStudy द्वारा परीक्षा-केंद्रित रूप में पुनर्लिखित की गई है (शब्दशः नकल नहीं)। हर तथ्य एवं आँकड़ा संरक्षित।

1 दृष्टि व उद्योग की स्थिति / Vision & Industry Status

- 2047 तक राजस्थान भारत का प्रमुख औद्योगिक व निवेश केंद्र — MSME, पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण व न्यूनतम नियामक बाधाओं पर बल; सतत खनन व पेट्रोलियम से आर्थिक विविधीकरण। By 2047, RJ a leading industrial & investment hub — focus on MSME, eco-friendly manufacturing & minimal regulatory hurdles; economic diversification via sustainable mining & petroleum.

GSVA में उद्योग का योगदान

Industry share in GSVA

संकेतक Indicator	स्थिर मूल्य (2011-12) Constant	प्रचलित मूल्य Current
GSVA (₹)	2.48 लाख करोड़	4.54 लाख करोड़
GSVA में योगदान (%)	28.21%	26.55%
वृद्धि	7.02%	6.99%
CAGR	4.36%	8.98%

उद्योग के उप-क्षेत्र (प्रचलित GSVA योगदान)

Sub-sectors (current GSVA share)

उप-क्षेत्र Sub-sector	योगदान Share	वृद्धि Growth
विनिर्माण Manufacturing	40.52%	+7.84%
निर्माण Construction	35.02%	+8.27%
खनन एवं उत्खनन Mining & quarrying	12.42%	-1.41%
विद्युत, गैस, जलापूर्ति Electricity, gas, water	12.04%	+9.37%

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) — आधार 2011-12, जारीकर्ता NSO

IIP — base 2011-12, by NSO

क्षेत्र Sector	भारंश Weight	IIP (2025-26) IIP
विनिर्माण Manufacturing	77.63%	181.17
खनन Mining	14.37%	87.94
विद्युत Electricity	7.99%	161.00
सामान्य सूचकांक General Index	100%	153.29

2 संस्थागत संरचना / Institutional Structure

- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग: स्थापना 1949, नाम परिवर्तन 19 अगस्त 2021। Dept of Industries & Commerce: est. 1949, renamed 19 Aug 2021.

- BIP (निवेश संवर्धन ब्यूरो): 1991; बड़े निवेश प्रस्तावों हेतु सचिवालय — Board of Investment (अध्यक्ष: मुख्यमंत्री) व State Empowered Committee (अध्यक्ष: मुख्य सचिव)। BIP (Bureau of Investment Promotion): 1991; secretariat for Board of Investment (chair: CM) & State Empowered Committee (chair: CS).
- RIICO (1980): औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था। RAJSICO (जून 1961, HQ जयपुर): हस्तशिल्प, लघु उद्योग ऋण; एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर (1979 से); झईपोर्ट — जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। RIICO (1980): apex for industrial development. RAJSICO (Jun 1961, Jaipur): handicraft & SSI loans; Air Cargo Complex Jaipur (since 1979); dry ports — Jaipur, Bhilwara, Jodhpur.
- RFC (राजस्थान वित्त निगम, 1955): MSME को वित्तीय सहायता। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र: वर्तमान 43 + 6 उप-केंद्र। RFC (1955): MSME finance. District Industries Centres: 43 + 6 sub-centres.

3 औद्योगिक क्षेत्र, पार्क व SIR / Industrial Areas, Parks & SIRs

- रीको द्वारा अब तक 445 औद्योगिक क्षेत्र विकसित; 2025-26 (दिसंबर तक) 19 नए औद्योगिक क्षेत्र — भीलवाड़ा (6), अजमेर (4), कोटा (2), अलवर/धौलपुर/उदयपुर/बारां/बांसवाड़ा/बीकानेर/बालोतरा (1-1)। RIICO has developed 445 industrial areas; 19 new in 2025-26 (by Dec) — Bhilwara (6), Ajmer (4), Kota (2), one each in Alwar/Dholpur/Udaipur/Baran/Banswara/Bikaner/Balotra.

विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) व प्रमुख पार्क

Special Investment Regions & Key Parks

- JPMIA (जोधपुर-पाली-मारवाड़): पाली के 9 गाँव, ~154 वर्ग किमी; SIR घोषित; RIICO = विकास प्राधिकरण। JPMIA: 9 villages of Pali, ~154 sq km; declared SIR; RIICO = development authority.
- KBNIR (खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना): 165 वर्ग किमी, पूर्ववर्ती अलवर के 43 गाँव; 28 दिसंबर 2020 को SIR घोषित। KBNIR: 165 sq km, 43 villages of erstwhile Alwar; declared SIR on 28 Dec 2020.
- HRRL डाउनस्ट्रीम हेतु राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ); इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क (जमवारामगढ़-थौलाई जयपुर व गुंदी-फतेहपुर कोटा); स्टोन पार्क गुंदी-फतेहपुर कोटा; सोलर पैनल पार्क काकाणी जोधपुर। Rajasthan Petro Zone (RPZ) for HRRL downstream; Integrated Resource Recovery Parks (Jamwaramgarh-Tholai Jaipur & Gundi-Fatehpur Kota); Stone Park; Solar Panel Park Kakani Jodhpur.
- 2 सिरेमिक एवं ग्लास जोन — सोनियाना (चित्तौड़गढ़) व गजनेर (बीकानेर); हस्तशिल्प-फर्नीचर पार्क बोरानाडा जोधपुर; फिनटेक पार्क व यूनिटी मॉल जयपुर; अग्निशमन केंद्र-9 (रीको)। 2 ceramic-glass zones — Soniana (Chittorgarh) & Gajner (Bikaner); handicraft-furniture park Boranada Jodhpur; Fintech Park & Unity Mall Jaipur; 9 fire stations (RIICO).

4 कनेक्टिविटी (WDFC, DMIC) / Connectivity (WDFC, DMIC)

- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC): दादरी (UP) से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (मुंबई); कुल लंबाई 1,504 किमी; लगभग 39% भाग राजस्थान के 28 जिलों से; सहायता — जापान। WDFC: Dadri (UP) to JNPT (Mumbai); total 1,504 km; ~39% through 28 districts of Rajasthan; assisted by Japan.
- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC): WDFC के दोनों ओर 150 किमी पट्टी विकसित। राजस्थान में प्रथम चरण नोड — KBNIR (165 किमी², SIR 28 दिसंबर 2020) व JPMIA (154 किमी², SIR 12 अक्टूबर 2020)। DMIC: 150-km belt on both sides of WDFC. RJ phase-1 nodes — KBNIR (165 km², SIR 28 Dec 2020) & JPMIA (154 km², SIR 12 Oct 2020).
- इनके विकास हेतु SPV — राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (RIDCO) की स्थापना 15 मार्च 2022। SPV — Rajasthan Industrial Corridor Development Corporation (RIDCO) set up on 15 March 2022.

5 प्रमुख नीतियाँ (RIPS, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर) / Key Policies (RIPS, Logistics, Data Centre)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS) (RIPS 2024)

अवधि

Period: लॉन्च 8 अक्टूबर 2024; 31 मार्च 2029 तक

Launched 8 Oct 2024; till 31 Mar 2029

न्यूनतम निवेश

Min. investment: विनिर्माण ₹50 करोड़; सेवा ₹25 करोड़; MSME ₹25 करोड़; पर्यटन ₹10 करोड़

Mfg ₹50 cr; service ₹25 cr; MSME ₹25 cr; tourism ₹10 cr

प्रोत्साहन

Incentive: निवेश सब्सिडी 7 वर्ष तक राज्य करों में 75% प्रतिपूर्ति; कस्टमाइज्ड पैकेज — Silver (₹500 करोड़+), Gold (₹1000 करोड़+/800 रोजगार), Platinum (₹3000 करोड़+/1500 रोजगार)

75% state-tax reimbursement for 7 yrs; Silver (₹500 cr+), Gold (₹1000 cr+/800 jobs), Platinum (₹3000 cr+/1500 jobs)

प्रगति

Progress: 2025-26 (दिसंबर तक) ₹1.65 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र

3,914 units (₹1.65 lakh cr proposed investment) given eligibility certificates by Dec 2025-26

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 (RJ Logistics Policy 2025)

जारी/प्रोत्साहन

Issued/Incentive: 31 मार्च 2025; पूंजीगत सब्सिडी EFCI का 25% (₹5-50 करोड़/वर्ष) या 7% ब्याज सब्सिडी; ग्रीन लॉजिस्टिक्स 50% (₹12.5 करोड़ तक)

31 Mar 2025; 25% capital subsidy (₹5-50 cr/yr) or 7% interest; green logistics 50% (up to ₹12.5 cr)

राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 (RJ Data Centre Policy 2025)

अधिसूचित

Notified: 19 फरवरी 2025; डेटा सेंटर को ESMA के तहत आवश्यक सेवा घोषित; 24x7 संचालन की अनुमति

19 Feb 2025; data centres declared essential service under ESMA; 24x7 operation allowed

6 MSME / MSME

नई परिभाषा (1 अप्रैल 2025 से)

New definition (from 1 Apr 2025)

वर्ग Class	निवेश Investment	टर्नओवर Turnover
सूक्ष्म Micro	₹2.5 करोड़	₹10 करोड़
लघु Small	₹25 करोड़	₹100 करोड़
मध्यम Medium	₹125 करोड़	₹500 करोड़

- MSME Act 2006; 14 सूक्ष्म-लघु उद्यम सुविधा परिषद; उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020; दिसंबर 2025 तक 4.41 लाख इकाइयाँ पंजीकृत। राजस्थान MSME अधिनियम 2019 (17 जुलाई 2019): अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र (5 वर्ष तक निरीक्षण से छूट); पोर्टल — राज उद्योग मित्र। MSME Act 2006; 14 facilitation councils; Udyam portal 1 Jul 2020; 4.41 lakh units registered by Dec 2025. RJ MSME Act 2019 (17 Jul 2019): Acknowledgement Certificate (5-yr inspection exemption); portal — Raj Udyog Mitra.

डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (Dr Ambedkar Dalit-Tribal Enterprise Promotion)

विवरण

Detail: 8 सितंबर 2022; SC/ST; ब्याज अनुदान — ₹25 लाख तक 9%, ₹25 लाख-5 करोड़ 7%, ₹5-10 करोड़ 6%

8 Sep 2022; SC/ST; interest subsidy — 9% up to ₹25 lakh, 7% (₹25 lakh-5 cr), 6% (₹5-10 cr)

PM विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)

विवरण

Detail: 17 सितंबर 2023; 18 ट्रेड; टूलकिट ₹15,000; बिना गारंटी ₹1 लाख (18 माह) + ₹2 लाख (30 माह) 5% ब्याज; राज्य +2% अनुदान (प्रभावी 3%); राजस्थान — ऋण स्वीकृति/वितरण में राष्ट्रीय द्वितीय, टूलकिट वितरण में तृतीय
17 Sep 2023; 18 trades; ₹15,000 toolkit; collateral-free ₹1 lakh + ₹2 lakh at 5%; state +2% (effective 3%); RJ 2nd nationally in loan sanction

युवा उद्यमिता / विश्वकर्मा युवा उद्यमी (VKYUPY) (Yuva Udyamita / VKYUPY)

युवा उद्यमिता

Yuva Udyamita: 2023-24; 45 वर्ष तक; 1,000 इकाई लक्ष्य; ₹2 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान
2023-24; up to 45 yrs; 1,000 units; 6% subsidy up to ₹2 cr

VKYUPY

VKYUPY: 3 सितंबर 2025; ₹1 करोड़ तक 8%, ₹1-2 करोड़ 7% ब्याज; मार्जिन मनी 25% या ₹5 लाख
3 Sep 2025; 8% up to ₹1 cr, 7% (₹1-2 cr); margin money 25% or ₹5 lakh

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) 2026 (MM Yuva Swarajgar (MYSY) 2026)

विवरण

Detail: 15 जनवरी 2026; 18-45 वर्ष; 1 लाख युवा लक्ष्य; 8-12 पास: सेवा/व्यापार ₹3.5 लाख, विनिर्माण ₹7.5 लाख; स्नातक/ITI: सेवा ₹5 लाख, विनिर्माण ₹10 लाख; मार्जिन मनी 10%
15 Jan 2026; 18-45 yrs; 1 lakh youth; 100% interest subsidy + 10% margin money

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना / MSME नीति 2024 (Integrated Cluster Dev / MSME Policy 2024)

क्लस्टर

Cluster: 8 दिसंबर 2024; 15 क्लस्टर लक्ष्य; CFC हेतु 90% या ₹10 करोड़; भिवाड़ी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ₹146 करोड़ केंद्र सहायता
8 Dec 2024; 15 clusters; CFC 90% or ₹10 cr; ₹146 cr central aid for Bhiwadi waste mgmt

MSME नीति 2024

MSME Policy 2024: 8 दिसंबर 2024 (MSME नीति 2022 प्रतिस्थापित); ₹50 करोड़ तक ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान
8 Dec 2024 (replaced 2022 policy); +2% interest subsidy up to ₹50 cr loan

7 ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस व निर्यात / Ease of Doing Business & Exports

- राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो अधिनियम 2011 के तहत राज निवेश पोर्टल (One Stop Shop) — ₹10 करोड़+ निवेश प्रस्ताव; 19 विभागों की 181 सेवाएं एकीकृत। Raj Nivesh Portal (One Stop Shop) under RJ Enterprises Single Window Act 2011 — ₹10 cr+ proposals; 181 services of 19 departments.
- BRAP 2024 (DPIIT): राजस्थान — Business Entry, Labor Regulation Enablers, Environment Registration व Service Sector श्रेणियों में 'टॉप अचीवर'। BRAP 2026: 15 नवंबर 2025 – 15 जुलाई 2026। BRAP 2024 (DPIIT): RJ 'Top Achiever' in Business Entry, Labor Regulation Enablers, Environment Registration & Service Sector. BRAP 2026: 15 Nov 2025 – 15 Jul 2026.

निर्यात स्थिति (2024-25)

Export status (2024-25)

- कुल निर्यात ₹97,171.66 करोड़ (~₹97,000 करोड़); सर्वाधिक — Engineering Goods ₹19,849.29 करोड़। Total exports ₹97,171.66 cr; highest — Engineering Goods ₹19,849.29 cr.
- शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं: 1. इंजीनियरिंग गुड्स, 2. जेम्स एंड ज्वेलरी, 3. धातुएं, 4. वस्त्र, 5. हस्तशिल्प — कुल योगदान 67%+। Top 5: engineering goods, gems & jewellery, metals, textiles, handicrafts — 67%+ of exports.

निर्यात व व्यापार नीतियाँ (Export & Trade Policies)

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024

Export Promotion 2024: 31 मार्च 2029 तक; प्रथम बार निर्यातकों को RIPS-2024 के तहत माल भाड़ा पर 25% सब्सिडी (₹25 लाख तक)
Till 31 Mar 2029; 25% freight subsidy for first-time exporters under RIPS (up to ₹25 lakh)

ODOP नीति 2024

ODOP 2024: 8 दिसंबर 2024; प्रत्येक जिले से निर्यात उत्पाद; DEPC (जिला कलेक्टर अध्यक्ष)

8 Dec 2024; one export product/district; DEPC chaired by Collector

व्यापार संवर्धन नीति 2025 / वस्त्र-परिधान नीति 2025

Trade Promotion 2025 / Textile 2025: व्यापार संवर्धन 7 दिसंबर 2025 (₹1 करोड़ 6%, ₹1-2 करोड़ 4% ब्याज); वस्त्र-परिधान 13 फरवरी 2025

Trade Promotion 7 Dec 2025; Textile & Apparel 13 Feb 2025

8 राइजिंग राजस्थान व प्रवासी / Rising Rajasthan & Diaspora

- राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024: 9-11 दिसंबर 2024, JECC सीतापुरा जयपुर; थीम — Replete, Responsible, Ready; 20,000+ निवेशक; 13 विशेष सत्र; ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024: 9-11 Dec 2024, JECC Sitapura Jaipur; theme Replete, Responsible, Ready; 20,000+ investors; 13 sessions; ₹35 lakh crore proposals.
- राजस्थान फाउंडेशन: 26 चैप्टर सक्रिय + 14 नए घोषित; प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 (जयपुर); प्रवासी हितों हेतु DOAR विभाग (Domestic & Overseas Rajasthani Affairs) गठित। Rajasthan Foundation: 26 chapters + 14 new; first Pravasi Rajasthani Diwas 10 Dec 2025 (Jaipur); DOAR department formed for diaspora.
- प्रवासी राजस्थानी नीति 2025: जारी 10 दिसंबर 2025; 5 स्तंभ — Accelerate, Bridge, Celebrate, Drive, Ensure। Pravasi Rajasthani Policy 2025: issued 10 Dec 2025; 5 pillars — Accelerate, Bridge, Celebrate, Drive, Ensure.

9 खनन क्षेत्र / Mining Sector

- राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का भंडारण; 57 का वर्तमान में वाणिज्यिक उत्पादन। 82 mineral types in Rajasthan; 57 commercially produced.
- अग्रणी उत्पादक: चूना पत्थर, सीसा-जस्ता, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट, बैराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर व तांबा। मार्बल, सैंडस्टोन व ग्रेनाइट में प्रमुख स्थान। Leading producer of limestone, lead-zinc, wollastonite, garnet, barytes, silica sand, granite, marble & copper; prominent in marble, sandstone & granite.

RSMML (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि.) (RSMML)

विवरण

Detail: स्थापना 30 अक्टूबर 1974; राज्य PSU; 4 SBU-PC — रॉक फॉस्फेट (झामरकोटड़ा, उदयपुर), जिप्सम (बीकानेर), लिग्नाइट (जयपुर), लाइमस्टोन (जोधपुर)

Est. 30 Oct 1974; state PSU; 4 SBU-PCs — rock phosphate (Jhamarkotra, Udaipur), gypsum (Bikaner), lignite (Jaipur), limestone (Jodhpur)

RSMET / DMFT (RSMET / DMFT)

RSMET

RSMET: सितंबर 2020; खान व भू-विज्ञान विभाग को तकनीकी परामर्श; 2025-26 में 34 सर्वेक्षण परियोजनाएं

Sep 2020; technical advice; 34 survey projects in 2025-26

DMFT

DMFT: अधिसूचना 2016; प्रत्येक जिले में (31 मई 2016) → राज्य में 33 DMFT; खनन प्रभावित क्षेत्रों का हित

Notified 2016; in every district (31 May 2016) → 33 DMFTs; welfare of mining-affected areas

राजस्थान खनिज नीति 2024 (RJ Mineral Policy 2024)

जारी/लक्ष्य

Issued/Targets: 4 दिसंबर 2024; 2047 तक 1 करोड़+ रोजगार; खनिज निष्कर्षण 58→70; 50 खनिज ब्लॉक नीलामी; खनन रियायत क्षेत्र 2% तक;

लिथियम/दुर्लभ पृथ्वी तत्व को बढ़ावा

4 Dec 2024; 1 crore+ jobs by 2047; mineral extraction 58→70; 50 block auctions; mining area to 2%; promote lithium/REE

राजस्थान M-Sand नीति 2024 (RJ M-Sand Policy 2024)

विवरण

Detail: प्रथम M-Sand नीति 2020; 25 जनवरी 2021 को उद्योग दर्जा; रॉयल्टी 50% छूट; निवेश सब्सिडी 75% (10 वर्ष); बिजली शुल्क 100% (7 वर्ष); 2028-29 तक 50% उपयोग लक्ष्य

First M-Sand policy 2020; industry status 25 Jan 2021; 50% royalty rebate; 75% investment subsidy (10 yrs); 100% electricity duty exemption (7 yrs); 50% use by 2028-29

10 तेल, गैस एवं रिफाइनरी / Oil, Gas & Refinery

- राजस्थान देश में ऑनशोर (स्थलीय) प्राकृतिक गैस उत्पादन में दूसरे स्थान पर; कच्चे तेल उत्पादन में ~12% योगदान; देश के कुल 28.70 MMTPA में से ~3.42 MMTPA कच्चा तेल। RJ 2nd in onshore natural-gas production; ~12% of national crude; ~3.42 MMTPA of national 28.70 MMTPA crude.
- 4 पेट्रोलियम बेसिन (14 जिले, ~1.50 लाख वर्ग किमी): बाड़मेर-सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर-नागौर, विंध्यन। 15 तेल-गैस क्षेत्रों से 57,000-59,000 BOPD; प्रमुख क्षेत्र — मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी। 4 petroleum basins (14 districts, ~1.50 lakh sq km): Barmer-Sanchor, Jaisalmer, Bikaner-Nagaur, Vindhyan. 57,000-59,000 BOPD from 15 fields; key fields Mangala, Bhagyam, Aishwarya, Saraswati, Raageshwari, Kameshwari.

राजस्थान रिफाइनरी (बाड़मेर) (Rajasthan Refinery (Barmer))

विवरण

Detail: शुभारंभ 16 जनवरी 2018 (पचपद्रा, बालोतरा); क्षमता 9 MMTPA; JV — HPCL 74% (₹19,600 करोड़) : राजस्थान सरकार 26% (₹6,886 करोड़); ऋण-इक्विटी 2:1; संशोधित लागत ₹79,459 करोड़; BS-6 मानक; देश की पहली रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स

Launched 16 Jan 2018 (Pachpadra, Balotra); 9 MMTPA; JV HPCL 74% (₹19,600 cr) : RJ 26% (₹6,886 cr); debt-equity 2:1; revised cost ₹79,459 cr; BS-6; India's first refinery-cum-petrochemical complex

दोहन कंपनियाँ व CGD नीति (Operators & CGD Policy)

दोहन

Operators: बाड़मेर-सांचौर बेसिन — केयर्न इंडिया (16 क्षेत्र; मंगला 29 अगस्त 2009); जैसलमेर बेसिन — वेदांता/ONGC Barmer-Sanchor — Cairn India (16 fields; Mangala 29 Aug 2009); Jaisalmer — Vedanta/ONGC

CGD नीति 2025

CGD Policy 2025: राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति — 16 जुलाई 2025; PNG व CNG उपलब्धता विस्तार

City Gas Distribution Policy — 16 Jul 2025; expand PNG & CNG availability

11 रोजगार / Employment

- PLFS 2023-24 (NSO): राज्य में WPR (कार्यशील जनसंख्या अनुपात) व LFPR में क्रमिक वृद्धि। क्षेत्रवार सर्वाधिक श्रमिक — कृषि-वानिकी-मत्स्य 51.05% (भारत 46.07%), निर्माण 12.31%, विनिर्माण 10.95%, थोक-खुदरा व्यापार 8.61%; न्यूनतम — रियल एस्टेट 0.14%। PLFS 2023-24 (NSO): WPR & LFPR rising. Sector-wise workers — agri-forestry-fishing 51.05% (India 46.07%), construction 12.31%, manufacturing 10.95%, wholesale-retail 8.61%; lowest — real estate 0.14%.

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (MM Yuva Sambal Yojana)

विवरण

Detail: 1 फरवरी 2019 (संशोधित 1 जनवरी 2022); स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता — पुरुष ₹4,000/माह, महिला/ट्रांसजेंडर/विशेष योग्यजन ₹4,500/माह; अधिकतम 2 वर्ष; 3 माह कौशल प्रशिक्षण + 4 घंटे इंटरशिप

1 Feb 2019 (revised 1 Jan 2022); allowance ₹4,000/mo (men), ₹4,500/mo (women/transgender/disabled); max 2 yrs; 3-mo skill training + 4-hr internship

EPFO नई पहल (2025-26) (EPFO new initiatives (2025-26))

PMVBRY

PMVBRY: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना — 1 अगस्त 2025; भाग A (प्रथम बार रोजगार, वेतन ₹1 लाख तक, ₹15,000 तक एकमुश्त); भाग B (नियोक्ता को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000/माह, विनिर्माण हेतु 4 वर्ष)

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana — 1 Aug 2025; Part A (first job, wage ≤ ₹1 lakh, up to ₹15,000); Part B (₹3,000/mo per extra employee to employer)

EPFO योजनाएं

EPFO schemes: कर्मचारी नामांकन अभियान 1 नवंबर 2025; EPF 1952, EPS 1995, EDLI 1976 (मृत्यु पर ₹2.5-7 लाख)

Enrolment campaign 1 Nov 2025; EPF 1952, EPS 1995, EDLI 1976 (₹2.5-7 lakh on death)

रोजगार नीतियाँ (Employment Policies)

रोजगार नीति 2026

Employment Policy 2026: 12 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस); विजन 2030 तक \$350 बिलियन अर्थव्यवस्था; मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार; पोर्टल EEMS 2.0

12 Jan 2026; vision \$350 bn economy by 2030; 15 lakh jobs by Mar 2029; EEMS 2.0 portal

GCC / कौशल नीति 2025

GCC / Skill Policy 2025: GCC नीति 27 नवंबर 2025; कौशल नीति 16 अप्रैल 2025; मॉडल कैरियर सेंटर 16 जिलों में

GCC Policy 27 Nov 2025; Skill Policy 16 Apr 2025; Model Career Centres in 16 districts

12 श्रमिक कल्याण व कौशल / Labour Welfare & Skill

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

Building & Construction Workers Welfare Board

- गठन 2009 (BOCW अधिनियम 1996 के तहत)। प्रमुख सहायता: सामान्य मृत्यु ₹2 लाख, दुर्घटना मृत्यु ₹5 लाख, पूर्ण विकलांगता ₹3 लाख, आंशिक ₹1 लाख; औजार/टूलकिट ₹2,000; सुलभ आवास ₹1.50 लाख; शुभ शक्ति योजना (अविवाहित पुत्री) ₹55,000; सिलिकोसिस ₹3 लाख + मृत्यु पर आश्रित ₹2 लाख। Constituted 2009 (BOCW Act 1996). Aid: natural death ₹2 lakh, accidental ₹5 lakh, full disability ₹3 lakh, partial ₹1 lakh; toolkit ₹2,000; housing ₹1.50 lakh; Shubh Shakti (unmarried daughter) ₹55,000; silicosis ₹3 lakh + ₹2 lakh to dependents.
- बच्चों हेतु: शिक्षा छात्रवृत्ति ₹8,000-25,000 व प्रोत्साहन ₹4,000-35,000; IIT/IIM ट्यूशन फीस पुनर्भरण; IAS प्रारंभिक पास ₹1 लाख, RAS ₹50,000। प्रसूति सहायता: पुत्र ₹20,000, पुत्री ₹21,000। ई-श्रम पोर्टल — 26 अगस्त 2021 (असंगठित श्रमिक, 16-59 वर्ष)। For children: scholarship ₹8,000-25,000 & incentive ₹4,000-35,000; IIT/IIM fee reimbursement; IAS prelims ₹1 lakh, RAS ₹50,000. Maternity: son ₹20,000, daughter ₹21,000. e-Shram portal — 26 Aug 2021 (unorganized workers, 16-59).

आजीविका व कौशल विकास

Livelihood & Skill Development

- RMOL (राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड): 17 अगस्त 2010 — आजीविका मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य; मई 2012 में RSLDC (राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम) में परिवर्तित। RMOL: 17 Aug 2010 — RJ was the first state to launch a livelihood mission; became RSLDC in May 2012.
- DDU-GKY: 15-35 वर्ष (विशेष वर्ग 45 तक); आरक्षण — SC/ST 34%, महिला 33%, अल्पसंख्यक 9%, दिव्यांग 5%। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (अम्ब्रेला) — राजकिविक (RSTP), सक्षम, समर्थ। DDU-GKY: ages 15-35 (45 for special groups); reservation SC/ST 34%, women 33%, minority 9%, disabled 5%. MM Skill Dev (umbrella) — Rajkivik, Saksham, Samarth.
- मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY): 7 नवंबर 2019; RSLDC + कॉलेज शिक्षा; 45 कोर्स, 350 घंटे (90 घंटे सॉफ्ट स्किल)। मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य (पूर्व नाम I-AM शक्ति)। ITEES सिंगापुर सहायता से पर्यटन प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र (उदयपुर); PDOT केंद्र 5 जिलों में। MMYKY: 7 Nov 2019; RSLDC + Higher Ed; 45 courses, 350 hrs (90 hrs soft skill). MM Nari Shakti Kaushal Samarthya (formerly I-AM Shakti). Tourism CoE at Udaipur (ITEES Singapore); PDOT in 5 districts.
- राजस्थान युवा नीति 2026: 12 जनवरी 2026; 15-29 वर्ष; 2.25-2.30 करोड़ युवा (राज्य की 27.2% जनसंख्या)। RJ Youth Policy 2026: 12 Jan 2026; ages 15-29; 2.25-2.30 crore youth (27.2% of population).

प्रमुख खेल आयोजन (2025)

Major sports events (2025)

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025: 24 नवंबर-5 दिसंबर 2025, राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर; 24 खेल विधाएं। Khelo India University Games 2025: 24 Nov-5 Dec 2025, at all RJ divisional HQs; 24 disciplines.
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 (बिहार): राजस्थान 60 पदक (24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य) — तृतीय स्थान। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 (उत्तराखंड): राजस्थान 43 पदक (9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य) — 15वां स्थान। Khelo India Youth Games 2025 (Bihar): RJ 60 medals (24G, 12S, 24B) — 3rd. 38th National Games 2025 (Uttarakhand): RJ 43 medals (9G, 11S, 23B) — 15th.

खिलाड़ी कल्याण व अवसंरचना

Athlete welfare & infrastructure

- खेल जीवन बीमा: अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को ₹25 लाख तक दुर्घटना व जीवन बीमा। एक जिला-एक खेल योजना; डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल (खेल प्रमाण-पत्र)। Sports Life Insurance: up to ₹25 lakh for international medallists. One District-One Sport; Digital Repository portal.
- राजस्थान राज्य खेल परिषद 25 आवासीय खेल अकादमियां संचालित (कोच मानदेय ₹13,500 → ₹25,000/माह); सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर 'युवा साथी केंद्र' (दिसंबर 2025 तक); SMS स्टेडियम जयपुर में High Performance Sports Training & Rehab Centre। State Sports Council runs 25 residential sports academies (coach honorarium ₹13,500 → ₹25,000/mo); 'Yuva Sathi Kendra' at all 7 divisional HQs; High-Performance Sports Training & Rehab Centre at SMS Stadium Jaipur.

★ अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs

1. GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान (प्रचलित मूल्यों पर) कितना है?

Industry's share in GSVA (current prices)?

1. 28.21%
2. 26.55% ✓
3. 40.52%
4. 12.42%

व्याख्या: प्रचलित मूल्यों पर 26.55% (स्थिर मूल्य 28.21%)।
26.55% at current (28.21% at constant).

2. उद्योग के उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक GSVA योगदान किसका है?

Largest sub-sector in industry GSVA?

1. निर्माण
2. विनिर्माण ✓
3. खनन
4. विद्युत-गैस

व्याख्या: विनिर्माण 40.52% (निर्माण 35.02%, खनन 12.42%, विद्युत 12.04%)।
Manufacturing 40.52%.

3. IIP का आधार वर्ष कौन-सा है व जारीकर्ता कौन है?

IIP base year & issuing agency?

1. 2011-12; NSO ✓
2. 2004-05; CSO
3. 2017-18; NSO
4. 2011-12; RBI

व्याख्या: आधार वर्ष 2011-12; NSO द्वारा मासिक जारी; सामान्य सूचकांक 153.29।
Base 2011-12; by NSO; general index 153.29.

4. रीको द्वारा अब तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए?

Industrial areas developed by RIICO so far?

1. 154
2. 445 ✓
3. 43
4. 19

व्याख्या: 445 औद्योगिक क्षेत्र; 2025-26 में 19 नए जोड़े गए।
445; 19 new added in 2025-26.

5. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है?

Total length of WDFC?

1. 1,504 किमी ✓
2. 165 किमी
3. 154 किमी
4. 2,800 किमी

व्याख्या: 1,504 किमी (दादरी-JNPT); ~39% राजस्थान के 28 जिलों से; सहायता जापान।
1,504 km; ~39% through 28 RJ districts; Japan-assisted.

6. DMIC के लिए स्थापित SPV कौन-सा है व कब बना?

DMIC SPV — name & year?

1. RIICO; 1980
2. RIDCO; 15 मार्च 2022 ✓
3. BIP; 1991
4. RSMML; 1974

व्याख्या: राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (RIDCO) — 15 मार्च 2022।
RIDCO — 15 Mar 2022.

7. RIPS 2024 कब लॉन्च हुई?

When was RIPS 2024 launched?

1. 8 अक्टूबर 2024 ✓
2. 8 दिसंबर 2024
3. 31 मार्च 2025
4. 19 फरवरी 2025

व्याख्या: 8 अक्टूबर 2024; 31 मार्च 2029 तक प्रभावी।
8 Oct 2024; valid till 31 Mar 2029.

8. MSME की नई परिभाषा (1 अप्रैल 2025) में सूक्ष्म उद्यम की निवेश सीमा?

Micro-enterprise investment limit (new MSME definition)?

1. ₹1 करोड़
2. ₹2.5 करोड़ ✓
3. ₹25 करोड़
4. ₹125 करोड़

व्याख्या: सूक्ष्म: निवेश ₹2.5 करोड़, टर्नओवर ₹10 करोड़।
Micro: ₹2.5 cr investment, ₹10 cr turnover.

9. उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर दिसंबर 2025 तक कितनी इकाइयाँ पंजीकृत हैं?

Units registered on Udyam portal by Dec 2025?

1. 3,914
2. 4.41 लाख ✓
3. 445
4. 1.65 लाख

व्याख्या: 4.41 लाख औद्योगिक इकाइयाँ; उद्यम पोर्टल 1 जुलाई 2020।
4.41 lakh units; Udyam portal from 1 Jul 2020.

10. PM विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई व इसमें कितने ट्रेड हैं?

PM Vishwakarma — launch & number of trades?

1. 17 सितंबर 2023; 18 ट्रेड ✓
2. 8 सितंबर 2022; 14 ट्रेड
3. 1 जुलाई 2020; 21 ट्रेड
4. 15 जनवरी 2026; 18 ट्रेड

व्याख्या: 17 सितंबर 2023; 18 ट्रेड; टूलकिट ₹15,000; राज्य +2% ब्याज अनुदान।
17 Sep 2023; 18 trades; ₹15,000 toolkit.

11. राजस्थान से कुल निर्यात (2024-25) लगभग कितना रहा?

Total exports from RJ (2024-25)?

1. ₹35 लाख करोड़
2. ₹97,171.66 करोड़ ✓
3. ₹19,849 करोड़
4. ₹1.65 लाख करोड़

व्याख्या: ₹97,171.66 करोड़; सर्वाधिक इंजीनियरिंग गुड्स (₹19,849.29 करोड़)।
₹97,171.66 cr; top engineering goods.

12. राइजिंग राजस्थान समिट 2024 कब व कहाँ आयोजित हुई?

Rising Rajasthan Summit 2024 — when & where?

1. 9-11 दिसंबर 2024, जयपुर ✓
2. 14-27 नवंबर 2025, दिल्ली
3. 10 दिसंबर 2025, जयपुर
4. 8 अक्टूबर 2024, जोधपुर

व्याख्या: 9-11 दिसंबर 2024, JECC सीतापुरा जयपुर; ₹35 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव।
9-11 Dec 2024, JECC Jaipur; ₹35 lakh cr proposals.

13. राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का वाणिज्यिक उत्पादन होता है?

How many minerals are commercially produced in RJ?

1. 82
2. 57 ✓
3. 70
4. 33

व्याख्या: 82 खनिजों का भंडारण; 57 का वाणिज्यिक उत्पादन।
82 stored; 57 commercially produced.

14. RSMML की स्थापना कब हुई?

RSMML established?

1. 30 अक्टूबर 1974 ✓
2. 1980
3. सितंबर 2020
4. 1955

व्याख्या: 30 अक्टूबर 1974; 4 SBU-PC (रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लिग्नाइट, लाइमस्टोन)।
30 Oct 1974; 4 SBU-PCs.

15. राजस्थान खनिज नीति 2024 का खनिज निष्कर्षण लक्ष्य (2047)?

Mineral extraction target by 2047 (Policy 2024)?

1. 58 से 70 ✓
2. 50 ब्लॉक
3. 2% भूमि
4. 1 करोड़ रोजगार

व्याख्या: खनिज निष्कर्षण 58 से बढ़ाकर 70; 2047 तक 1 करोड़+ रोजगार।
Raise extraction 58→70; 1 crore+ jobs by 2047.

16. राजस्थान ऑनशोर प्राकृतिक गैस उत्पादन में देश में किस स्थान पर है?

RJ rank in onshore natural-gas production?

1. प्रथम
2. दूसरा ✓
3. तीसरा
4. चौथा

व्याख्या: दूसरा स्थान; कच्चे तेल में ~12% योगदान।

2nd; ~12% of national crude.

17. राजस्थान रिफाइनरी (बाड़मेर) में JV हिस्सेदारी क्या है?

Rajasthan Refinery JV stakes?

1. HPCL 74% : राज्य 26% ✓
2. ONGC 50% : राज्य 50%
3. राज्य 74% : HPCL 26%
4. वेदांता 60% : राज्य 40%

व्याख्या: HPCL 74% (₹19,600 करोड़) : राजस्थान 26% (₹6,886 करोड़); 9 MMTPA; पचपदरा।

HPCL 74% : RJ 26%; 9 MMTPA; Pachpadra.

18. PLFS 2023-24 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक श्रमिक किस क्षेत्र में?

Sector with most workers (PLFS 2023-24)?

1. विनिर्माण
2. कृषि-वानिकी-मत्स्य ✓
3. निर्माण
4. थोक-खुदरा

व्याख्या: कृषि-वानिकी-मत्स्य 51.05% (भारत 46.07%)।

Agri-forestry-fishing 51.05% (India 46.07%).

19. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में महिला को बेरोजगारी भत्ता?

Yuva Sambal allowance for women?

1. ₹4,000/माह
2. ₹4,500/माह ✓
3. ₹3,000/माह
4. ₹5,000/माह

व्याख्या: महिला/ट्रांसजेंडर/विशेष योग्यजन ₹4,500/माह; पुरुष ₹4,000/माह।

Women/transgender/disabled ₹4,500/mo; men ₹4,000/mo.

20. आजीविका मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है?

First state to launch a livelihood mission?

1. राजस्थान ✓
2. केरल
3. मध्य प्रदेश
4. गुजरात

व्याख्या: राजस्थान — RMOL (17 अगस्त 2010), जो 2012 में RSLDC बना।

Rajasthan — RMOL (17 Aug 2010), became RSLDC in 2012.

21. 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 (उत्तराखंड) में राजस्थान का स्थान?

RJ rank at 38th National Games 2025?

1. तृतीय
2. 15वां ✓
3. प्रथम
4. 10वां

व्याख्या: 15वां स्थान, 43 पदक (9 स्वर्ण); खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तृतीय।

15th, 43 medals; 3rd at Khelo India Youth Games.

22. राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मार्च 2029 तक रोजगार लक्ष्य?

Jobs target by March 2029 (Employment Policy 2026)?

1. 10 लाख
2. 15 लाख ✓
3. 1 करोड़
4. 5 लाख

व्याख्या: 15 लाख रोजगार; विजन — 2030 तक \$350 बिलियन अर्थव्यवस्था।

15 lakh jobs; vision \$350 bn economy by 2030.
